गोपाल सिंह

बनाम

उत्तराखंड राज्य

(2013 की आपराधिक अपील संख्या 291)

फ़रवरी 08, 2013

(जी.एस. सिंघवी और दीपक मिश्रा, जे.जे.)

दंड संहिता, 1860 - धारा 324 - आरोपी-अपीलकर्ता के विरूद्ध दोषसिद्धि - देशी पिस्तौल ('कट्टा) से पीडब्लू3 पर गोली चलाने के लिए, जिससे उसे आग्नेयास्त्र से चोट लगी। दोषसिद्धि का औचित्य - निर्णय उचित - पीडब्लू-1 ने स्पष्ट रूप से कहा कि अपीलकर्ता ने देशी कट्टे से गोली चलाई थी जो उसके भतीजे पीडब्लू- 3 को लगी - इसी तरह, पीडब्लू-3 के पिता पीडब्लू 2 ने घटना का स्पष्ट रूप से वर्णन किया - पीडब्लू 3 की गवाही कि जब उनके चाचा, पीडब्लू-1, अपनी दुकान में हिसाब-किताब तैयार कर रहे थे, तो अचानक अपीलकर्ता द्वारा चलाई गई गोली उन्हें लग गई - चिकित्सीय साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो गया कि चोट बन्दूक से लगी थी - जांच अधिकारी पीडब्लू-5 ने गवाही दी कि उसने घटना स्थल, दुकान के कमरे की दीवार से 'कट्टा के छर्रे बरामद किए थे - बचाव पक्ष द्वारा इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इन परिस्थितियों में, केवल इसलिए कि ' ' ,

अभियोजन पक्ष की बात पर अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए - चोट की प्रकृति और इस्तेमाल किए गए हथियार को ध्यान में रखते हुए, आईपीसी की धारा 324 के तहत अपीलकर्ता की सजा को उचित ठहराया गया था

सज़ा / सज़ा - अभियुक्त-अपीलकर्ता ने पीडब्लू-3 पर गोली चलाई, जिससे बाद वाले को आग्नेयास्त्र से चोट लगी - अपीलकर्ता को धारा 324 के तहत दोषी ठहराया गया और 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई - बचाव पक्ष द्वारा अत्यधिक सजा को चुनौती दी गई - निर्णयः विधानमण्डल द्वारा धारा 324 आईपीसी के अपराध में तीन साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान किया गया है। विधायिका का इरादा ऐसे अपराध के संबंध में सजा देने में न्यायपालिका को विवेक प्रदान करना है जहां उसने न्यूनतम सजा प्रदान नहीं की है या इसे सशर्त बना दिया है परंतु निहित विवेकाधिकार को ठोस तथ्यों के आधार पर तर्क संगत अवधारणाओं में समाहित होने की आवश्यकता है। इस मामले में, डॉक्टर ने चोट को गंभीर नहीं बताया, बल्कि इसके विपरीत उल्लेख किया कि कोई फ्रैक्चर नहीं था और केवल मांसपेशियों में चोट थी - इस्तेमाल किया गया हथियार (देशी पिस्तौल) धारा 324 आईपीसी के विवरण के अंतगर्त आता है - घटना लगभग 20 साल पहले हुई थी - पक्षकारान पड़ोसी थे और यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था कि अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास था - तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता में, 1 वर्ष आर एल यु/एस की सजा धारा 324 आईपीसी के तहत

पर्याप्त होगी - इसके अलावा, अपीलकर्ता को सीआरपीसी की धारा 357(3) - दंड संहिता, 1860 - धारा 324 के तहत परिकल्पित मुआवजे के रूप में पीड़ित को 20000/- रु. का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

सजा / सजा - उचित सजा - अपराध और सजा के बीच आनुपातिकता का सिद्धांत - निर्णयः सजा असंगत रूप से अत्यधिक नहीं होनी चाहिए - आनुपातिकता की अवधारणा न्यायाधीश को महत्वपूर्ण विवेक की अनुमति देती है लेकिन इसे कुछ सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए - इसमें कोई जैकेट फॉर्मूला या गणितीय सटीकता में हल करने योग्य सिद्धांत नहीं लगाया जा सकता यह मामले के तथ्यों और तर्कसंगत न्यायिक विवेक पर निर्भर करेगा - विवेक को उचित सजा के वैचारिक सार में अंतर्निहित किया जाना चाहिए।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि आरोपी-अपीलकर्ता ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर पीडब्लू-1 पर हाथों, मुक्कों और पत्थरों से हमला किया और उसकी दुकान से पैसे निकाल लिए और उसकी जेब से भी पैसे निकाल लिए और पीडब्लू-3 पर गोलियां चलाईं, जिससे वह घायल हो गया। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 307, 324 और 380 के तहत दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 307 और 380 के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया, लेकिन यह मानते हुये कि अपीलकर्ता ने पीडब्लू-3 पर बंदूक की गोली चलाई थी, आईपीसी की धारा

324 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा और इस आधार पर उसे तीन साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई।

इस अपील में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि यह निष्कर्ष कि उसने गोली चलाई थी, उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ है क्योंकि 'कट्टा (देशी पिस्तौल जिससे गोली चलाई गई थी) को जब्त नहीं किया गया था। विकल्प में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि चोट की प्रकृति, घटना के समय अपीलकर्ता की उम्र और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को ध्यान में रखते हुए कि कोई फ्रैक्चर नहीं था और मांसपेशियों की चोट को छोड़कर कोई चोट नहीं थी, उस पर अधिरोपित किया गया तीन साल का कारावास अत्यधिक था।

कोर्ट ने अपील का निपटारा करते हुए

यह निर्णय दिया कि: 1. पीडब्लू-1 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलकर्ता ने अपनी देशी पिस्तौल से गोली चलाई थी जो उसके भतीजे पीडब्लू-3 को लगी थी। इसी प्रकार, घायल पीडब्लू-3 के पिता पीडब्लू-2 ने घटना का सजीव वर्णन किया है। पीडब्लू-3 की गवाही में यह आया है कि जब उनके चाचा, पीडब्लू-1, अपनी दुकान में हिसाब-किताब तैयार कर रहे थे, तो अचानक अपीलकर्ता द्वारा चलाई गई गोली उन्हें लग गई। चिकित्सकीय साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि चोट बन्दूक से लगी थी। पीडब्लू-5, जांच अधिकारी ने गवाही दी है कि उसने घटना स्थल, दुकान के कमरे

की दीवार से 'कट्टा के छर्रे बरामद किए थे। बचाव पक्ष की ओर से इसके लिए कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में, केवल इसलिए कि' ' , अभियोजन पक्ष की बात पर अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए। सत्र न्यायाधीश ने चोट की प्रकृति और इस्तेमाल किए गए हथियार को ध्यान में रखते हुए आरोपी को आईपीसी की धारा 324 के तहत दोषी ठहराया, जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। न तो विश्लेषण में और न ही उस स्कोर पर दर्ज निष्कर्ष में कोई भ्रांति है।

(पैरा 12,13) (112-जी; 113-ए-डी, एच; 114-बी)

अनवारुल हक बनाम यूपी राज्य। (2005) 10 एससीसी 581 : 2005 (3) एससीआर 917 - पर भरोसा किया गया।

2.1. बस सजा ही समाज की सामूहिक पुकार है. जहां सामूहिक पुकार को दिमाग में सबसे ऊपर रखना होगा, साथ ही अपराध और सजा के बीच आनुपातिकता के सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। अनुपातिक रूप से सज़ा अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। आनुपातिकता की अवधारणा न्यायाधीश को महत्वपूर्ण विवेकाधिकार की अनुमति देती है लेकिन इसे कुछ सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। कुछ मामलों में, दोष की प्रकृति, अभियुक्त का पूर्व आचरण, उम्र का तथ्य, दोषी की भविष्य में अपराधी बनने की क्षमता, उसके सुधार की क्षमता और प्रचलित

परिवेश में स्वीकार्य जीवन जीने की क्षमता, एक सामाजिक खतरा या उपद्रव बनने की प्रवृति का प्रभाव और कभी-कभी अपराध में समय की चूक, पार्टियों के बीच संबंध और दोषी को मूल्य आधारित सामाजिक प्रवाह में लाने के सिद्धांत की आकर्षकता, मार्गदर्शक कारक हो सकते हैं। गणितीय सटीकता या कोई स्ट्रेट-जैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता है। यह मामले के तथ्यों और तर्कसंगत न्यायिक विवेक पर निर्भर होगा।

(पैरा 18) (117-सी-जी)

2.2. आईपीसी की धारा 324 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में विधायिका ने सजा का प्रावधान किया है जो तीन साल तक हो सकती है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। विधायी मंशा ऐसे अपराध के संबंध में सजा देने में न्यायपालिका को विवेक प्रदान करना है जहां उसने न्यूनतम सजा प्रदान नहीं की है या इसे सशर्त बना दिया है। निहित विवेक को कल्पना के दायरे में घूमने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, बल्कि ठोस तथ्यों पर आधारित तर्कसंगत अवधारणाओं में अंतर्निहित होना आवश्यक है।

(पैरा 23) (119-ई-एफ)

2.3. मौजूदा मामले में, डॉक्टर ने चोट को गंभीर नहीं बताया है, बल्कि इसके विपरीत, उन्होंने उल्लेख किया है कि कोई फ्रैक्चर नहीं है और केवल मांसपेशियों में चोट है। इस्तेमाल किया गया हथियार आईपीसी की

धारा 324 के तहत दिए गए विवरण में सटीक बैठता है। घटना करीब 20 साल पहले की है. पार्टियां पड़ोसी हैं और यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास था। तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, तथ्यात्मक स्कोर प्राप्त करने में आईपीसी की धारा 324 के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा पर्याप्त होगी। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं को पीड़िता को सीआरपीसी की धारा 357(3) के तहत मुआवजे के तौर पर 20,000/- रु. का भुगतान करना होगा। उक्त राशि ट्रायल जज के समक्ष जमा की जाएगी जो उचित पहचान पर पीड़ित के पक्ष में इसका वितरण करेगा।

(पैरा 24) (119-जी; 120-ए-सी)

संता सिंह बनाम पंजाब राज्य (1976) 4 एससीसी 190: 1977 (1) एससीआर 229 ; जमील बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010) 12 एससीसी 532: 2009 (15) एससीआर 712; शैलेश जसवन्तभाई और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य (2006) 2 एससीसी 359: 2006 (1) एससीआर 477 ; गुरु बसवराज बनाम कर्नाटक राज्य

(2012) 8 एससीसी 734 ; धर्म पाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1993 एस सी 2484: मेरमभाई पंजाबभाई खाचर और अन्य बनाम गुजरात राज्य एआईआर 1996 एस सी 3236 और पारा सीनैया

और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (2012) 6 एस सी सी 800 - पर आधारित।

केस कानून संदर्भ:

2005 (3) एससीआर 917 पर भरोसा पैरा 12

1977 (1) एससीआर 229 पर भरोसा पैरा 14

2009 (15) एससीआर 712 पर भरोसा पैरा 15

2006 (1) एससीआर 477 पर भरोसा पैरा 16

(2012) 8 एससीसी 734 पर भरोसा पैरा 17

एआईआर 1993 एससी 2484 पर भरोसा पैरा 20

एआईआर 1996 एससी 3236 पर भरोसा पैरा 21

(2012) 6 एससीसी 800 पर भरोसा पैरा 22

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2013 की आपराधिक अपील संख्या 291

2001 की आपराधिक अपील संख्या 137 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय,

नैनीताल के निर्णय और आदेश दिनांक 15.03.2012 से।

अपीलार्थी की ओर से सुनील कुमार भारती।

प्रतिवादी की ओर से अभिषेक अत्रे

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

दीपक मिश्रा, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. विशेष अनुमति द्वारा की गई इस अपील में, अपीलकर्ता ने दोषसिद्धि के फैसले और दिनांक 15.3.2012 को पारित सजा के आदेश की कानूनी सार्थकता पर सवाल उठाया है।

2001 की आपराधिक अपील संख्या 137 में नैनीताल में उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने, जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने 1994 के सत्र परीक्षण संख्या 24 में सीखा सत्र न्यायाधीश, अल्मोडा द्वारा भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में "आईपीसी) की धारा 307 और 380 के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया है, लेकिन धारा 324 आईपीसी के अंतर्गत दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा है।

3. इस अपील के निर्णय के लिए जिन तथ्यों को बताया जाना आवश्यक है, वे यह हैं कि प्रेम सिंह, पीडब्लू-2 द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 20.10.1992 को लगभग 9.00 बजे रात्री में, गोली की आवाज सुनकर और साथ ही अपने भाई गोपाल सिंह, पीडब्लू-1 की चीख सुनकर कि उसके साथ मारपीट की जा रही है

और उसकी जान को खतरा है, वह गोपाल सिंह की दुकान पर गया और पाया कि आरोपी गोपाल सिंह और उसका भाई पूरन सिंह उसे हाथ, मुक्कों और पत्थरों से पीट रहे थे। उसने देखा कि हमलावरों का पिता हर सिंह दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ दुकान के बाहर खड़ा है। यह आरोप लगाया गया था कि प्रेम सिंह के बेटे नारायण सिंह, पीडब्लू-3 को गोली लगी थी। सूचनाकर्ता और उसका भतीजा सुरेंद्र सिंह घायल गोपाल सिंह और नारायण सिंह को रानीखेत अस्पताल ले गए। आगे आरोप लगाया गया कि आरोपी व्यक्तियों ने पीडब्लू-1 की दुकान से 25,000/- रुपये और उसकी जेब से 1200/- रुपये निकाल लिए थे। मालूम हो कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने के बाद पटवारी विलेख के समक्ष प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।

आपराधिक कार्यवाही आरम्भ होने के बाद, जांच अधिकारी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत गवाहों के बयान दर्ज किए, साइट प्लान, एक्सटेंशन-7 तैयार किया, छर्रे बरामद किए, खून से सने कपड़े जब्त किए घायल व्यक्तियों और उनकी गवाह पीडब्लू-4 की डॉक्टर से जांच करवाई गई, और अंततः, जांच पूरी होने पर, आईपीसी की धारा 147, 148, 452, 307 और 395 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप-पत्र विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष रखा गया, जिन्होंने बदले में, मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया।

4. आरोपी व्यक्तियों ने अपने अपराध से इनकार कर दिया और दुश्मनी के कारण झूठे आरोप लगाने की दलील दी, जो गोपाल सिंह द्वारा लड़े गए ग्राम सभा चुनाव में हर सिंह के उत्पीड़न पर आधारित थी। बता दें कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही पूरन सिंह की मृत्यु हो गई तथा मुकदमा आरोपी व्यक्तियों, गोपाल सिंह और हर सिंह के खिलाफ अण्वीक्षा चालू रही।

5. अभियोजन पक्ष ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए पांच गवाहों की जांच की, अर्थात् गोपाल सिंह, पीडब्लू-1, घायल, पूरन सिंह, पीडब्लू-2, घायल के भाई, नारायण सिंह, पीडब्लू-3, जिन्हें गोली लगी थी, डॉ. एन. के पाण्डे गवाह पीडब्लू-4 जिन्होने घायलों की जांच की थी तथा पीडब्लू-5 बच्ची सिंह अनुसंधान अधिकारी जिन्होने दस्तावेज प्रदर्शित कराये बचाव पक्ष ने अपनी दलील के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं करने का फैसला किया।

6. विद्वान सत्र न्यायाधीश ने रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री के आधार पर हर सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया। हालाँकि, उन्होंने अभियुक्त गोपाल सिंह को आईपीसी की धारा 307, 324 और 380 के तहत पीडब्लू 1,3,4 और आंशिक रूप से पीडब्लू-2 की गवाही पर विश्वास करते हुए दोषी ठहराया और उसे सात साल, एक साल और चार साल के कठोर कारावास

की सजा सुनाई। क्रमशः उक्त इस शर्त के साथ कि सभी सजा में समवर्ती होंगे।

7. उपरोक्त दोषसिद्धि और सजा से व्यथित होकर, आरोपी अपीलकर्ता ने 2001 की आपराधिक अपील संख्या 137 को प्राथमिकता दी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि गोपाल सिंह को बंदूक की गोली से चोट नहीं लगी थी, लेकिन चोटें मुक्के, लात और घूसों के कारण लगी थीं। पत्थरों के कारण उक्त घायल की 10वीं पसली में फ्रैक्चर हो गया। हालाँकि, उच्च न्यायालय की राय थी कि पूरन सिंह ने वही साधन और वही बल प्रयोग किया होगा और जैसा उसने किया था। मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई, तो अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देने की सलाह दी गई। इस दृष्टिकोण से यह निष्कर्ष निकला कि अपीलकर्ता आईपीसी की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी नहीं है। इस समय, हम यह कह सकते हैं कि इस संबंध में उच्च न्यायालय का विश्लेषण सही है या नहीं, इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राज्य ने विवादित फैसले की आलोचना नहीं की है। इसलिए, हम इसे वहीं छोड़ने के लिए मजबूर हैं

8. जैसा कि स्पष्ट है, उच्च न्यायालय ने पाया है कि अपीलकर्ता ने नारायण पर गोली चलाई थी। उक्त अपराध के लिए विद्वान ट्रायल न्यायाधीश ने उसे आईपीसी की धारा 324 के तहत दोषी ठहराया था और

तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने उस संबंध में विद्वान सत्र न्यायाधीश के विश्लेषण में कोई खामी नहीं पाई और उसी पर अपनी मुहर लगा दी। जहां तक धारा 380 के तहत दोषसिद्धि का सवाल है, उच्च न्यायालय ने आरोपी-अपीलकर्ता को बरी कर दिया।

9. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री सुनील कुमार भारती ने तर्क दिया कि यह निष्कर्ष कि अपीलकर्ता ने गोली चलाई थी, उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ है, क्योंकि 'कट्टा (देशी पिस्तौल जिससे गोली चलाई गई थी) को जब्त नहीं किया गया है। . वैकल्पिक रूप से उनके द्वारा यह आग्रह किया गया है कि चोट की प्रकृति, घटना के समय अपीलकर्ता की उम्र, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत कि कोई फ्रैक्चर नहीं था और मांसपेशियों की चोट को छोड़कर कोई चोट नहीं थी, को ध्यान में रखते हुए, तीन साल की कठोर कारावास अत्यधिक है और यह कम किये जाने योग्य है।

10. राज्य के विद्वान वकील डॉ. अभिषेक अत्रे ने दोषसिद्धि के फैसले के साथ-साथ सजा के आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत किया कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने गवाहान की गवाही का सही विश्लेषण किया है, जिन्होंने घटना के बारे में गवाही दी है और आगे इस तथ्य यह ध्यान दिलाया है कि गोपाल सिंह की दुकान के कमरे की दीवार से गोली की बरामदगी हुई है और तदनुसार, यह राय दी गई है कि नारायण सिंह को चोट आरोपी द्वारा 'कट्टा (देशी पिस्तौल) से चलाई गई गोली से लगी थी

और इसलिए, उस आधार पर निकाले गए निष्कर्ष में गलती नहीं पाई जा सकती। अत्यधिक सजा देने से संबंधित वैकल्पिक तर्क को पूरा करते हुए, राज्य के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि वर्तमान प्रकृति के मामले में, तीन साल के कठोर कारावास को अनुपातहीन नहीं माना जा सकता है।

11. सबसे पहले, हम यह भी कह सकते हैं कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा एक जवाबी मामला दायर किया गया था, लेकिन एफआईआर में यह आरोप नहीं था कि गोली प्रेम सिंह की लाइसेंसी बंदूक से चलाई गई थी और अंततः उक्त दोषमुक्ति में समाप्त हुआ।

12. रिकॉर्ड पर साक्ष्य के आधार पर, यह ध्यान देने योग्य है कि पीडब्लू-1 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आरोपी गोपाल सिंह ने अपनी देशी पिस्तौल से गोली चलाई थी जो उसके भतीजे नारायण सिंह को लगी थी। जिरह में पता चला कि पूर्व सैनिक नारायण सिंह के पिता प्रेम सिंह लाइसेंसी बंदूक धारक हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह घटना उनके दुकान के कमरे के अंदर घटी थी। इन बिंदुओं पर कोई जिरह नहीं हुई है। इसी तरह घायल नारायण सिंह के पिता प्रेम सिंह ने घटना का सजीव वर्णन किया है. जिरह मूल रूप से दुश्मनी और पैसे की चोरी से संबंधित है। पीडब्लू-3 घायल नारायण सिंह है। उनकी गवाही में आया है कि जब उनके चाचा गोपाल सिंह अपनी दुकान में हिसाब-किताब तैयार कर रहे थे तो अचानक आरोपी गोपाल सिंह द्वारा गोली चलाई गई। यह ध्यान रखना

दिलचस्प है कि गवाही से जो पता चला है वह यह है कि उसके पिता के पास एक लाइसेंसी बंदूक थी। चिकित्सीय साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि चोट बन्दूक से लगी थी। पीडब्ल्यू-5, जांच अधिकारी ने गवाही दी है कि उसने घटना स्थल, दुकान के कमरे की दीवार से 'कट्टा के छर्रे बरामद किए थे। इन परिस्थितियों में, हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि केवल इसलिए कि 'कट्टा बरामद नहीं हुआ है, अभियोजन पक्ष की बात पर अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, हम लाभ के लिए अनवारुल हक बनाम यूपी राज्य 1 के फैसले का हवाला दे सकते हैं, जिसमें यह माना गया था कि केवल इसलिए कि अपराध करने में जिस चाकू का इस्तेमाल किया गया था, वह बरामद नहीं हुआ था।

जाँच अभियोजन पक्ष के उन गवाहों के साक्ष्यों की उपेक्षा करने का कारक नहीं हो सकती, जिन्होंने हथियार के उपयोग के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त होकर गवाही दी थी। इसके अलावा, अदालत ने डॉक्टर के साक्ष्य का भी हवाला दिया जिसमें हथियार के इस्तेमाल के बारे में बताया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि अदालत ने कहा कि हालांकि हथियार के बारे में डॉक्टर की राय सैद्धांतिक थी, फिर भी इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त के संबंध में, इस न्यायालय ने आईपीसी की धारा 324 के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा को बरकरार रखा, जैसा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी

13. हम यह स्पष्ट करने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि हम उपरोक्त कथन पर भरोसा कर रहे हैं क्योंकि मौजूदा मामले में डॉक्टर की साक्ष्य है कि चोट बंदूक की गोली से लगी है और छर्रे दुकान के कमरे की दीवारों से बरामद किए गए हैं तथा बचाव पक्ष द्वारा कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया गया है। जिरह में जो बात सामने आई है वह यह है कि घायल के पिता प्रेम सिंह के पास लाइसेंसी बंदूक थी। हम वास्तव में यह समझ पाने में असफल हैं कि उक्त उद्दीपन रक्षा में किस प्रकार सहायता प्रदान करेगा। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने विचार करते हुए

चोट की प्रकृति और इस्तेमाल किए गए हथियार के आधार पर आरोपी को आईपीसी की धारा 324 के तहत दोषी ठहराया गया है, जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। हमें न तो विश्लेषण में और न ही उस निष्कर्ष में कोई भ्रांति नजर आती है

14. अपीलकर्ता के विद्वान वकील का वैकल्पिक निवेदन यह है कि जब विद्वान सत्र न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने केवल यह पाया है कि धारा 324 के तहत दोषसिद्धि टिकाऊ है, तो तीन साल के कठोर कारावास की सजा नहीं दी जानी चाहिए थी इस संबंध में, सांता सिंह बनाम पंजाब राज्य 2 के फैसले का उल्लेख करना उपयोगी है जिसमें न्यायाधिपती श्री भगवती, जे. (तब उनका आधिपत्य था), धारा 235(2)

दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या करते हुए उचित सजा की अवधारणा की ओर विज्ञापित किया गया और इस प्रकार राय दी गईः -

"... एक उचित सजा कई कारकों का मिश्रण है जैसे कि अपराध की प्रकृति, परिस्थितियाँ - अपराध को कम करने या बढ़ाने वाली -, अपराधी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड, यदि कोई हो, अपराधी की उम्र, रोजगार के संबंध में अपराधी का रिकॉर्ड, शिक्षा, घरेलू जीवन, संयम और सामाजिक समायोजन के संदर्भ में अपराधी की पृष्ठभूमि, अपराधी की भावनात्मक और मानसिक स्थिति, अपराधी के पुनर्वास की संभावनाएं, अपराधी की समुदाय में सामान्य जीवन में वापसी की संभावना, अपराधी के उपचार या प्रशिक्षण की संभावना, यह संभावना कि सजा अपराधी या अन्य लोगों द्वारा अपराध को रोकने के रूप में काम कर सकती है और वर्तमान समुदाय की आवश्यकता, यदि कोई हो, विशेष प्रकार के अपराध के संबंध में इस तरह के निवारक के लिए। ये ऐसे कारक हैं जिन्हें उचित निर्णय लेने में अदालत द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए सजा हेतु, और, इसलिए, विधायिका ने महसूस किया कि, इस उद्देश्य के लिए, दोषसिद्धि के बाद एक अलग चरण प्रदान किया जाना चाहिए जब अदालत सजा पर असर डालने वाले इन कारकों के संबंध में आरोपी को सुन सकती है और फिर आरोपी को उचित सजा दे सकती है।"

पूर्व में इस न्यायालय के कई आदेशों में उक्त सिद्धांत का पालन किया गया है।

15. जमील बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 3 में इस न्यायालय ने यह कहकर सिद्धांत दोहराया कि सजा उचित और किए गए अपराध की गंभीरता के अनुपात में होनी चाहिए। सजा की अवधारणा के बारे में बोलते हुए, न्यायालय ने इस प्रकार कहाः -

"15. सजा प्रणाली के संचालन में, कानून को तथ्यात्मक मैट्रिक्स के आधार पर सुधारात्मक तंत्र या निवारण को अपनाना चाहिए। चतुराई से मॉड्यूलेशन द्वारा, सजा प्रक्रिया जहां होनी चाहिए वहां कठोर होनी चाहिए, और जहां आवश्यक हो वहां दया के साथ संयमित होना चाहिए। तथ्य और दी गई परिस्थितियां प्रत्येक मामले में, अपराध की प्रकृति, जिस तरीके से इसकी योजना बनाई गई और प्रतिबद्ध किया गया, अपराध करने का मकसद, आरोपी का आचरण, इस्तेमाल किए गए हथियारों की प्रकृति और अन्य सभी संबंधित परिस्थितियां प्रासंगिक तथ्य हैं जो विचार योग्य है

16. प्रत्येक न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह अपराध की प्रकृति और जिस तरीके से इसे निष्पादित या प्रतिबद्ध किया गया था, उसे ध्यान में रखते हुए उचित सजा दे। सजा सुनाने वाली अदालतों से अपेक्षा की जाती है कि वे सजा के सवाल से संबंधित सभी प्रासंगिक तथ्यों और

परिस्थितियों पर विचार करें और अपराध की गंभीरता के अनुरूप सजा देने के लिए आगे बढ़ें।''

उक्त मामले में, हड्डी टूट गई थी और ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 308 के तहत दोषी ठहराया था और उसे दो साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

16. शैलेश जसवन्तभाई और अन्य बनाम गुजरात राज्य व अन्य में, 4 न्यायालय ने इस प्रकार देख हैः

"कानून सामाजिक हितों को नियंत्रित करता है, परस्पर विरोधी दावों और मांगों पर मध्यस्थता करता है। लोगों के व्यक्तियों और संपत्ति की सुरक्षा राज्य का एक अनिवार्य कार्य है। इसे आपराधिक कानून के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। निस्संदेह, जहां एक अंतर-सांस्कृतिक संघर्ष है जीवित कानून को नई चुनौतियों का उत्तर ढूंढना होगा और अदालतों को चुनौतियों का सामना करने के लिए सजा प्रणाली को ढालना होगा। अराजकता का संक्रमण सामाजिक व्यवस्था को कमजोर कर देगा और इसे बर्बाद कर देगा। समाज की सुरक्षा और आपराधिक प्रवृत्ति को खत्म करना - कानून का उद्देश्य है। जिसे उचित सजा देकर हासिल किया जाना चाहिए। इसलिए, "व्यवस्था की इमारत की आधारशिला के रूप में कानून को समाज के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए। फ्रीडमैन ने अपने लॉ इन चेंजिंग सोसाइटी में कहा कि "आपराधिक कानून की

स्थिति - ऐसी होनी चाहिए - समाज की सामाजिक चेतना का एक निर्णायक प्रतिबिंब होनी चाहिये। " इसलिए, सजा प्रणाली के संचालन में, कानून को तथ्यात्मक मैट्रिक्स के आधार पर सुधारात्मक मशीनरी या निवारण को अपनाना चाहिए। चतुराई से मॉडुलन करके, सजा देने की प्रक्रिया जहां होनी चाहिए वहां कठोर होनी चाहिए, और जहां आवश्यक हो वहां दया से संयमित होना चाहिए। प्रत्येक मामले में तथ्य और परिस्थितियाँ, अपराध की प्रकृति, जिस तरह से इसकी योजना बनाई गई और प्रतिबद्ध किया गया, अपराध करने का मकसद, अभियुक्त का आचरण, इस्तेमाल किए गए हथियारों की प्रकृति और अन्य सभी परिस्थितियाँ विचार के करने हेतु प्रासंगिक है।

17. हाल ही में, इस न्यायालय ने गुरु बसवराज बनाम कर्नाटक राज्य, 5 में उचित वाक्य की अवधारणा पर चर्चा करते हुए सजा किया है किः

"यह देखना अदालत का कर्तव्य है कि अपराध होने और सामाजिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उचित सजा दी जाए। न्याय के लिए सामूहिक अपील जिसमें पर्याप्त सजा शामिल है, को हल्के से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।"

18. न्यायपूर्ण दण्ड ही समाज की सामूहिक पुकार है। यद्यपि सामूहिक आह्वान को सबसे ऊपर रखना होगा, साथ ही अपराध और सजा

के बीच आनुपातिकता के सिद्धांत को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। किसी अपराध के संबंध में उचित दंड का सिद्धांत सजा का आधार है। सज़ा अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। आनुपातिकता की अवधारणा न्यायाधीश को महत्वपूर्ण विवेकाधिकार की अनुमति देती है लेकिन इसे कुछ सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। कुछ मामलों में, दोषी की प्रकृति, अभियुक्त का पूर्ववृत्त, उम्र का तथ्य, दोषी की भविष्य में अपराधी बनने की क्षमता, उसके सुधार की क्षमता और प्रचलित परिवेश में स्वीकार्य जीवन जीने की क्षमता, प्रभाव - सामाजिक ख़तरा या उपद्रव बनने की प्रवृत्ति, और कभी-कभी अपराध की प्रकृति, पक्षों के बीच संबंध को ध्यान में रखते हुए अपराध करने और उसके आचरण में समय की चूक और दोषी को मूल्य-आधारित सामाजिक मुख्यधारा में लाने के सिद्धांत की आकर्षणशीलता मार्गदर्शक कारक हो सकती है। ज़ोर देने की आवश्यकता नहीं है, ये कुछ उदाहरणात्मक पहलू हैं जिन्हें संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। हम यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि न तो कोई स्ट्रेट-जैकेट फॉर्मूला हो सकता है और न ही कोई हल करने योग्य गणितीय सिद्धांत की सटीकता में। यह मामले के तथ्यों और तर्कसंगत न्यायिक विवेक पर निर्भर होगा। न तो किसी न्यायाधीश की व्यक्तिगत धारणा, न ही स्वयं-पालन वाली नैतिक दृष्टि और न ही काल्पनिक आशंकाओं को कोई खेल खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए। हर अपराध के लिए किसी कठोर उपाय के बारे में नहीं सोचा जा सकता। इसी प्रकार, किसी अपराधी के साथ

केवल न्यायालय में निहित विवेक के आधार पर नरमी बरतने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वास्तविक आवश्यकता उन परिस्थितियों को तौलना है जिनमें अपराध किया गया है और अन्य सहवर्ती कारकों को हमने यहां पहले भी इंगित किया है और इस न्यायालय द्वारा कई घोषणाओं में भी कहा गया है। ऐसी कसौटी पर सजा अधिरोपित की जानी चाहिए। विवेक कल्पना के दायरे में नहीं होना चाहिए। इसे उचित सज़ा के वैचारिक सार में समाहित किया जाना चाहिए।

19. एक न्यायालय को सजा सुनाते समय विभिन्न जटिल मामलों को ध्यान में रखना पड़ता है। सज़ा देने से संबंधित किसी पद्धति की संरचना की कल्पना करना कठिन है। विधायिका ने अपने विवेक से न्यायाधीश को विवेकाधिकार प्रदान किया है जो मामले के तथ्यात्मक परिदृश्य में तर्क संगत मापदडों द्वारा निर्देशित होता है। कुछ क्षेत्रों में विधायिका ने वह विवेकाधिकार प्रदान नहीं किया है और ऐसी परिस्थितियों में, विवेक सशर्त है। कुछ अपराधों के संबंध में पर्याप्त विशेष कारण बताकर सजा कम की जा सकती है। विशेष कारणों को वास्तविक विशेष परिस्थितियों पर आधारित होना चाहिए। इसलिए, ऐसी स्थितियों में न्यायालय का कर्तव्य जटिल हो जाता है। इसे एक ओर ला के नियम, सामूहिक विवेक और दूसरी ओर आनुपातिकता के सिद्धांत, सुधार के सिद्धांत और अन्य सहवर्ती कारकों के प्रति उचित सम्मान के साथ निष्पादित किया जाना चाहिए। यह कार्य कठिन हो सकता है, लेकिन इसे किसी भी प्रकार

के व्यक्तिगत दर्शन या व्यक्तिगत अनुभव या किसी प्राथमिक धारणा के बिना पूर्ण अनुभवजन्य तर्कसंगतता के साथ किया जाना चाहिए।

20. उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, हम उचित सजा की अवधारणा के संबंध में आईपीसी की धारा 324 के तहत इस न्यायालय द्वारा लगाई गई सजा के संबंध में दृष्टिकोण का उल्लेख करेंगे। धर्मपाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य 6 में, धारा 307 के तहत दोषसिद्धि को परिवर्तित करते हुए इस न्यायालय ने आईपीसी की धारा 324 के तहत दोषियों को एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा देना उचित समझा। ज्ञात हो, न्यायालय ने पाया कि यद्यपि अपीलकर्ताओं को लगी चोटें कुछ हद तक गंभीर थीं, फिर भी आईपीसी की धारा 307 के तहत दोषसिद्धि नहीं की गई।

21. मेरमभाई पुंजाभाई खाचर और अन्य बनाम गुजरात राज्य 7 में, जबकि इस न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि चोट गोली से लगी थी, आईपीसी की धारा 307 की सामग्री संतुष्ट नहीं थी और, तदनुसार, न्यायालय ने अपराध को परिवर्तित कर दिया। धारा 324 के तहत आरोपी को एक वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा और 1000 रुपये का जुर्माना तथा 1000/- रू अदा नहीं करने पर एक माह के लिये साधारण कारावास की सजा सुनाई।

22. पैरा सीनैया और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य 8 में, उसमें तथ्यात्मक मैट्रिक्स प्राप्त करने के संबंध में, आईपीसी की धारा 324 के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 1000/- रुपये का जुर्माना तथा अदम अदायगी में, तीन महीने के कारावास को उचित ठहराया गया।

23. इस मोड़ पर, हम दोहराव की कीमत पर दोहरा सकते हैं कि सज़ा का अधिरोपण, उन दृष्टांतों के अलावा, जिन्हें कम करने वाले कारक कहा गया है, कई अन्य कारकों पर निर्भर करेगा जो हर मामले में अलग-अलग होंगे। आईपीसी की धारा-324 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में विधायिका ने प्रावधान किया है। सज़ा जो तीन साल तक बढ़ सकती है या जुर्माना या दोनों से हो सकती है। विधायी मंशा, जैसा कि हम समझते हैं, ऐसे अपराध के संबंध में सजा देने में न्यायपालिका को विवेक प्रदान करना है जहां उसने न्यूनतम सजा प्रदान नहीं की है या इसे सशर्त नहीं बनाया है। हमने पहले ही इस बात पर प्रकाश डाला है कि निहित विवेक को कल्पना के दायरे में घूमने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, बल्कि ठोस तथ्यों पर आधारित तर्कसंगत अवधारणाओं में अंतर्निहित होना आवश्यक है।

24. मौजूदा मामले में, डॉक्टर ने चोट को गंभीर नहीं बताया है, बल्कि इसके विपरीत, उन्होंने उल्लेख किया है कि कोई फ्रैक्चर नहीं है और

केवल मांसपेशियों में चोट है। इस्तेमाल किया गया हथियार आईपीसी की धारा 324 के तहत दिए गए विवरण में सटीक बैठता है। घटना करीब 20 साल पहले की है। दोनों पक्ष पड़ोसी हैं और यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास था। तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता के संबंध में, हम यह उचित समझते हैं कि तथ्यात्मक स्कोर प्राप्त करने के लिए आईपीसी की धारा 324 के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा पर्याप्त होगी। इसके अलावा, हम यह निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ताओं को संहिता की धारा 357 (3) के तहत परिकल्पित मुआवजे के रूप में 20,000/- रुपये की राशि का भुगतान पीड़ित को करना होगा। उक्त राशि विद्वान ट्रायल न्यायाधीश के समक्ष जमा की जाएगी जो पीड़ित की उचित पहचान कर उसके पक्ष में वितरण करेगा

25. वाक्य में उपरोक्त संशोधन के साथ, अपील का निपटारा किया जाता है।

बी.बी.बी.

अपील निस्तारित

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक गीता चौधरी (न्यायिक अधिकारी) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंगेे्रजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।